संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1975

लोक सभा	–	पांचवीं लोक सभा
सत्र	–	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	–	श्री फख़रुद्दीन अली अहमद
भारत के उपराष्ट्रपति	–	श्री बी.डी. जत्ती
भारत की प्रधानमंत्री	–	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	–	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अगले वर्ष फिर मेहनत और लगन के साथ राष्ट्र की सेवा करने का बुलावा देता हूं।

पिछले चार वर्षों में नागहानी और भारी चुनौतियों का हिम्मत से मुकाबला करने के बाद हम बड़े साहस के साथ यह वर्ष शुरू कर रहे हैं। लगातार बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए, 1974 में सरकार की सबसे बड़ी चिन्ता यह रही कि अर्थव्यवस्था को पायदार बनाया जाए। मुद्रा-स्फीति पर काबू पाने के लिए सरकार ने एक व्यापक नीति अपनाई और जुलाई, 1974 से इसे अमल में लाया गया।

अधिक से अधिक साधन जुटाने और गैर-योजना खर्च में कमी करने के अलावा, एक उचित मुद्रानीति के जरिये मुद्रा-प्रसार पर रोक लगाई गई। स्मगलिंग, जमाखोरी और टैक्स इवेजन जैसे आर्थिक अपराधों तथा कम मिलने वाली चीजों का नकली माल बनाने वालों के खिलाफ एक जोरदार मुहिम चलाई गई। डिविडैंड्स की आमदनी को सीमित करके और बढ़ाई गई, मजदूरी वेतन और महंगाई भत्ते के एक हिस्से को रोके रखकर कन्जयूमर खर्च को काबू में रखा गया। सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया गया और अनाज, जरूरी कच्चा माल और दूसरे सामान को काफी मात्रा में आयात करने का बन्दोबस्त किया गया। 1974-75 की सालाना योजना पर फिर से गौर किया गया और उत्पादन बढ़ाने की गर्ज़ से जरूरी क्षेत्रों में खर्च की जाने वाली

रकम को बढ़ाया गया। पावर प्लांट्स, रेल ट्रांसपोर्ट, कोयला उत्पादन, इस्पात प्लांट्स और दूसरे सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की क्षमता को पूरी तरह काम में लाने के लिए जोरदार कार्रवाई की गई।

इन सब कार्रवाइयों के नतीजे सितम्बर, 1974 के आखिर में सामने आने शुरू हुए। कई राज्यों में वर्षा की कमी की वजह से खरीफ की फसल तसल्लीबख्श न होते हुए भी कीमतें गिरनी शुरू हुईं और मुद्रा-स्फीति को बढ़ावा देने वाले जरिये कमजोर पड़ने लगे। जरूरियातें जिंदगी की चीजों के मिलने में सुधार हुआ है और रबी की फसल अच्छी होने के आसार हैं।

इस माली साल के पहले नौ महीनों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है। थरमल प्लांट्स से चौदह फीसदी ज्यादा बिजली पैदा की जा रही है और डी.वी.सी. प्लांट्स से बिजली पैदा करने में चौंतीस फीसदी की बढ़ोतरी काबिले ज़िकर है, क्योंकि कई राज्यों में फिर भी बिजली की कमी पाई जाती है, पावर प्रोजेक्ट्स के पूरा करने के काम को जोरों से हाथ में लिया जा रहा है। 1974-75 में लगभग बीस लाख कि.वा. बिजली की क्षमता बढ़ाई जा रही है और तीस लाख अगले वर्ष में बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष एक करोड़ टन ज्यादा कोयला पैदा होगा। इस्पात का उत्पादन बढ़ रहा है और सरकारी क्षेत्र के इंजीनियरिंग उद्योग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अधिक रेल वैगन रोज़ाना चलाए जा रहे हैं।

मैं मजदूरों, किसानों और दूसरे तबके के लोगों को बधाई देता हूं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को पायदार बनाने के सरकारी प्रोग्रामों के समर्थन में पुख्ता इरादे, साहस और राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसार कार्य किया।

सरकार यह जानती है कि अभी आत्मसंतोष नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्ति और मांग के बीच अभी भी भारी असंतुलन है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में भी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता।

मुद्रा-संबंधी और माली सुधार के लिए जो कदम उठाये गये और आर्थिक अपराधों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसे जोरों से जारी रखा जाएगा। साथ-साथ सरकार यह कोशिश करेगी कि जरूरी क्षेत्रों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जायें और उत्पादन बढ़ाया जाये। हम विकासशील देशों और ऐसे विकसित देशों, जिन्होंने हमारी समस्याओं को समझने का परिचय दिया है, के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक न्यायपूर्ण और वायबल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपना काम जारी रखेंगे।

तेल, अनाज और रासायनिक खाद की कीमतें अचानक बढ़ जाने से हमें काफी धक्का लगा है। आम जरूरत की चीजों पर असर पड़ा है और इससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विदेशी-मुद्रा का काफी निकासन हुआ है।

1974-75 के पहले आठ महीनों में एक्सपोर्ट अर्निंग 36 फीसदी बढ़ी। फिर भी यह नुमायां बढ़ोतरी फॉरेन एक्सचेंज की कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। तेल आयात करने वाले विकासशील देशों की समस्यायें हल करने के लिए खास प्रयास और बन्दोबस्त जरूरी है। इस मामले में तेल निर्यात करने वाले कुछ देशों ने हमारी मदद की है। अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर भी कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन हालात को देखते हुए ये उपाय काफी नहीं हैं। यह मान्य होगा कि विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है और इसे ग्लोबल पैमाने पर दुनिया के सभी देशों के अर्थपूर्ण सहयोग से दूर करना होगा। बाइलेट्रल नैगोसियेशन और इंटरनेशनल फोरम्स के जरिये हम इस दिशा में उचित पहल जारी रखेंगे।

तेल का उत्पादन बढ़ाने और कोयले के इस्तेमाल पर जोर देने के अलावा, हमने तेल की खोज का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू कर दिया है। बम्बई हाई क्षेत्र में जो खोजें की गई हैं उनके नतीजे बहुत ही आशाजनक हैं। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस तेल-क्षेत्र का जल्दी से विकास किया जाए ताकि उत्पादन शुरू हो सके। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि 1976 में उत्पादन शुरू हो जाए और अगले चार वर्षों में इस क्षेत्र में एक करोड़ टन का उत्पादन हो सके। जल व थल दोनों ही इलाकों में तेल-उत्पादन का भविष्य बहुत आशाजनक है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ चिन्ता होना वाजबी है। योजना का एक ढांचा होता है और उद्देश्यों की एक सुसंगत प्रणाली होती है। इसके साथ तफसीली प्रोग्राम भी होता है जिससे लक्ष्यों और उनको प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनों का पता चलता है। पांचवीं योजना के बुनियादी ढांचे और इसके लक्ष्यों में कोई हेर-फेर नहीं किया गया है साथ ही देश और विदेश के आर्थिक क्षेत्रों में अनोखी घटनाओं को देखते हुए अपने प्रोग्राम में कुछ रद्दो-बदल करने की जरूरत है। इसी बीच 1975-76 की वार्षिक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जरूरी क्षेत्रों—कृषि-उत्पादन, सिंचाई, रासायनिक खाद, बिजली, इस्पात, कोयला और तेल खोज में अधिक धनराशि लगाने पर बल दिया जा रहा है। यह भी प्रस्ताव है कि विकास के उन प्रोग्रामों को बढ़ाया जाए जिनसे कम विकसित खण्डों और कमजोर वर्गों, जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी शामिल हैं, को फायदा पहुंचे। स्माल फार्मर्स डवलपमेंट एजेंसी और मार्जिनल फार्मर एण्ड एग्रीकलचरल लेबर, सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों और कमांड एरियास प्रोग्रामों को बढ़ाया जा रहा है।

1974 के राष्ट्रीय प्रयासों की समीक्षा परमाणु क्षेत्र में अपनी महान तरक्की का जिक्र किये बिना पूरी नहीं होगी। 18 मई, 1974 को जमीन के नीचे परमाणु विस्फोट किया गया था। मैं इस महान उपलब्धि के लिए परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को

बधाई देता हूं। हमने फिर से प्रतिज्ञा की है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल शांति के लिए ही किया जाएगा और इसके लिए सभी देशों ने हमारी सराहना की है। सरकार आर्थिक तरक्की लाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्वपूर्ण स्थान देती रहेगी।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ व्यापक रूप से बातचीत के ठोस नतीजे निकले हैं। इस संबंध में सरकार जल्दी ही घोषणा करेगी। हमारी कामना है कि राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में जम्मू-कश्मीर के लोग तेजी से तरक्की करें।

माननीय सदस्यगण, जब राष्ट्र महान चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जी-तोड़ कोशिश कर रहा है, यह दु:ख की बात है कि कुछ जमातों के लोग जनता के संकल्प को कमजोर करने और संयुक्त तथा समान उद्देश्य, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, को निष्फल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनका लक्ष्य पूर्ण क्रांति लाना और भ्रष्टाचार मिटाना है लेकिन असल में नतीजा यह रहा कि हिंसा फैली और राजनीतिक और आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न हुआ। सरकार इस बात को पूरी तरह जानती है कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत से क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। असल में, हमारा उद्देश्य है समाज में परिवर्तन लाना और जनजीवन के स्वभाव में सुधार लाना। लोकतंत्र की प्रणाली का यही सार है कि परिवर्तन ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श और आपसी समझौते के आधार पर ही लाया जाए। जब तक काबिले अमल कोई बेहतर तरीका सामने न रखा जाए मौजूदा व्यवस्था और संस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने से हमारे देश की पायदारी और तरक्की को खतरा होगा।

सरकार चाहती है कि लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक पर, जो कुछ समय से आपके सामने है, विचार हो और इस वर्ष इसे अंतिम रूप दिया जाए। इससे राजनीतिक प्रशासन में भ्रष्टाचार से निपटने का कानूनी आधार मिलेगा। सरकार चुनाव-कानून में संशोधन के प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जल्दी ही विचार-विमर्श करेगी। जो भी सुधार लाए जाएं वे ऐसे होने चाहिएं कि जहां तक हो सके उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिले और उनसे हमारे संविधान में रखी गई संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली मजबूत हो।

शिक्षा के मामले में भी, सरकार ने इम्तेहान के तरीकों में सुधार लाने, सेकेंडरी एजुकेशन को काम-धन्धों का आधार देने, उच्चतर शिक्षा के लिए एनरोलमेंट का असूल इख्त्यार करने और गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रणाली लागू करने के प्रोग्राम बनाए हैं। पिछले तजुर्बे से पता चलता है कि शिक्षा के सुधार की योजनाओं में तब तक तेज़ी नहीं आती जब तक राज्य सरकारें, शिक्षक, माता-पिता और विद्यार्थी इन्हें स्वीकार नहीं करते। इसी बीच लाखों नौजवानों के पढ़ाई के जीवन में काफी बेचैनी देखने में आई है। राज्य सरकारों ने सुधार के कुछ प्रोग्रामों को अमल में लाने के उपाय किए

हैं। हम यह चाहते हैं कि तालीम के तरीकों में अगर कोई बुनियादी तबदीली लानी है तो इसे पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद लाया जाए।

मैं सभी तबके के लोगों से अपील करता हूं कि वे इन बुनियादी सवालों पर संजीदगी से विचार करें, ठोस और रचनात्मक सुझाव सामने रखें और हल ढूंढ़ने के लिए सरकार को सहयोग दें। लोकतंत्र का यही तरीका है। कोई और तरीका अपनाने से गड़बड़ फैलेगी और कोई कारआमद नतीजा न निकलेगा।

अब मैं सिक्किम की घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। अप्रैल, 1974 में वहां पहली बार चुनाव हुए। सर्व-सम्मति से विधान सभा के प्रस्ताव पर 4 जुलाई, 1974 को चोग्याल की घोषणा के आधार पर नया संविधान लागू किया गया। सिक्किम की जनता की इच्छायें पूरी करने के लिए आपने सितम्बर, 1974 में संविधान संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें भारत और सिक्किम की मित्रता को मजबूत बनाने के लिए खास व्यवस्था थी और सिक्किम के प्रतिनिधियों को हमारी संसद में स्थान दिया गया। सिक्किम की जनता को, लोकतंत्र हासिल करने की अपनी इच्छाओं और आशाओं को रफ्ता-रफ्ता पूरा करने में कामयाब होने पर हम बधाई देते हैं।

हमने, विदेशों के साथ अपने संबंधों के मामले में स्वाभाविक तौर से अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंधों को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया है।

हमें दिसम्बर, 1974 में भूटान के राजा का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इस यात्रा से भारत और भूटान के बीच आपसी दोस्ती ज्यादा गहरी और मजबूत हुई।

पिछली मई में बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की यात्रा के दौरान, बंगला देश के साथ एक समझौता हुआ जो हमारे निकट संबंधों की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें सीमा के उन मसलों को हल किया गया जिन पर लगभग एक पीढ़ी से कोई फैसला नहीं हो पाता था। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों देश समझबूझ और सहयोग की उसी भावना से कोई भी मसला, जो सामने आये, सुलझाएंगे।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है। हम अगले महीने राष्ट्रपति दाउद के आने का इन्तजार कर रहे हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के दौरान, भारत-नेपाल संबंधों के मुख्तलिफ पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार हुआ। यह स्वीकार किया और एक-दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए बाइलेट्रल संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश करें।

मुझे इस बात पर खास तौर से संतोष है कि कच्चातीबू के मसले पर, पाक के मुहाने की समुद्री सीमा और श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के दर्जे के मामले में पुराने सवालों को मित्रतापूर्ण हल किया गया जिससे श्रीलंका और भारत की दोस्ती के ताल्लुकात और मजबूत हुए।

मालदीव और भारत के प्रधानमंत्रियों की एक-दूसरे के देश की यात्रा से दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंध मजबूत हुए।

मॉरिशस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम की यात्रा से, उस देश के साथ हमारे निकट संबंध और मजबूत होने में मदद मिली है।

अप्रैल, 1974 में बर्मा* के राष्ट्रपति ने-विन की सद्भावना यात्रा से आपसी सहयोग और समझ-बूझ को बढ़ावा मिला है।

पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाये गए हैं। प्रगति धीमी हुई है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। दोनों देशों के बीच डाक-सेवा, टेली-कम्यूनिकेशन, यात्रा-सुविधा और व्यापार फिर से शुरू करने पर समझौते हुए हैं। हमें आशा है कि एक-दूसरे से बातचीत करके और शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद दूर करने के अच्छे रवैये में तेजी आएगी और पाकिस्तान यह समझने की कोशिश करेगा कि मुख्तलिफ जरियों से हथियार जमा करके अपने आपको फिर से लैस करना बेसूद है, क्योंकि इससे आपसी मेल-मिलाप और इस उप-महाद्वीप में पायदार अमन कायम करने में रुकावट आयेगी।

इन्डोनेशिया के साथ कांटिनेटल शैल्फ बाऊन्ड्री एग्रीमेंट हुआ है। दिसम्बर, 1974 में मलेशिया के राजा और रानी का स्वागत करने का हमें फख्र हासिल हुआ। उनकी यात्रा से हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता और समझ-बूझ बढ़ने में मदद मिली।

पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की रफ्तार बढ़ी है। जापान के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण बने हुए हैं और हमारे व्यापार संबंध बढ़ते जा रहे हैं।

जैसा आप जानते हैं कि हमारी सरकार दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ औपचारिक तथा और ज्यादा सीधा संबंध कायम करने के उपाय कर रही है।

अरब देशों के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात बराबर की जिम्मेदारी और निकट सहयोग के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे और इराक, सूडान, अरब गणराज्य, संयुक्त अरब लघु गणराज्य जैसे कई अरब देशों के बीच बड़े से बड़े प्रतिनिधि मण्डलों की यात्राओं के दौरान हमने अपनी सामान्य नीतियों पर विचार-विमर्श किए और आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में कई समझौते हुए ।

पश्चिम एशिया की हालत गहरी चिन्ता का कारण है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक फिलिस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं किया जाता और हमला करके हथियाई गई अरबों की जमीन को वापस नहीं किया जाता। हम युनाइटेड नेशन्स में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की मौजूदगी का स्वागत करते हैं।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

हमारी प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा और ईरान के शहंशाह की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत हुए। हमने लम्बी अवधि वाली कई परियोजनाओं पर सहमति जाहिर की है जो आर्थिक और दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों को और निकट लाएगी।

दुनिया में मुक्ति और स्वतंत्रता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पुर्तगाल सरकार में परिवर्तन था। भारत और पुर्तगाल के बीच डिप्लोमैटिक संबंध फिर कायम करने पर एक समझौता हो गया है। हम उस देश के साथ मित्रता और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत का स्वागत करते हैं।

स्वतंत्रता की दिशा में अफ्रीकी लोगों की कामयाबी से एक नया युग शुरू हुआ है। पुर्तगाल की कुछ कालोनियां स्वतंत्रता के द्वार तक आ पहुंची हैं और कुछ में यह प्रोसैस शुरू हो गया है। साफ तौर से इन घटनाओं का रोडेशिया के गैर-कानूनी शासन पर असर पड़ा है। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिम्बाबवे में भी बहुमत शासन की स्थापना के लिए एक समझौता हो जाएगा और भेदभाव का अन्त होगा। दक्षिण अफ्रीका इस असर से बचा नहीं रह सकता। हमें पूरी उम्मीद है कि इन वाक्यात की तर्कसंगति और इसके नतीजे, जिन्हें टाला नहीं जा सकता, कालोनियलिज्म और जातिवाद के इस आखिरी गढ़ को साफ नजर आने लगेंगे और माननीय स्वतंत्रता के दमन और अन्य प्रकार के अत्याचारों का खात्मा होगा जिनके कारण मुहज़्ज़ब दुनिया ने उन्हें सेंसर किया है।

जाम्बिया के राष्ट्रपति, डॉ. केनेथ कौंडा और तनजानिया के उपराष्ट्रपति, श्री कवावा की यात्राओं से भारत और उन देशों के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग और मजबूत हुआ है।

आर्थिक और तकनीकी सहयोग से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के विकासशील देशों के साथ हम अपने संबंध मजबूत करना चाहते हैं। हमने कई क्षेत्रों में एक्सपरटाइज का विकास किया है और हमारे यहां सिखाई हुई और तजुर्बेकार मानव-शक्ति का विशाल भण्डार है और इस प्रकार आर्थिक विकास की दिशा में सहयोग के लिए विकासशील मित्र देशों की मांगों को पूरा करने की हममें क्षमता है। इसी प्रकार इनमें से कई देश कई तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। तेल की स्थिति का एक पॉजिटिव पहलू यह है कि इससे विकासशील देशों में आपसी सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं।

सभी राष्ट्रों के बीच मित्रता और नॉन-एलाइन्मैन्ट की हमारी नीति, और इस सब-कांटिनेंट में सामान्य स्थिति लाने का प्रोसैस तेज करने की हमारी पहल का सोवियत रूस द्वारा समर्थन किए जाने की हम बड़ी सराहना करते हैं। भारत-रूस सहयोग सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है।

1974 में, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणराज्य और हंगरी के प्रधानमंत्रियों का स्वागत करने का हमें सौभाग्य मिला। इन नेताओं के साथ विचार-विमर्श से हमारी आपसी समझबूझ बढ़ी है।

नॉन-एलायंड मूवमैंट में और यूनाइटेड नेशन्स और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों, पर भारत और यूगोस्लाविया ने निकट सहयोग बनाए रखा है।

अक्तूबर, 1974 में डॉ. हेनरी किसिंजर की भारत यात्रा के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच बेहतर समझ-बूझ और परिपक्व संबंध की आपसी इच्छा जाहिर की गई थी। एक संयुक्त भारत-अमरीका आयोग की स्थापना की गई है, जिससे सहयोग के लिए संस्थागत आधार मिलेगा। हमें आशा है कि संयुक्त राज्य अमरीका इस सब-कांटिनेंट में आम हालात पैदा करने की दिशा में कोशिश करता रहेगा और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इस पर उल्टा असर पड़े।

यूरोपियन इकोनामिक कम्युनिटी विकास की समस्याओं के प्रति अधिक प्रगतिशील और उदार पालीसी अपना रही है। भारत का एक तिहाई से ज्यादा व्यापार इस कम्युनिटी के मुल्कों के साथ है और हम उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ख्वाहिशमन्द हैं।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ हमारे संबंध, एशियाई प्रश्नों पर बढ़ती हुई समझबूझ के आधार पर निकट और खुशगवार बने रहे हैं। ये दोनों देश हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाए रखने की जरूरत के संबंध में तटवर्ती राज्यों की चिन्ता से सहमत हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसे हम बहुत महत्व देते हैं।

हमारा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था का संकट और विकासशील देशों की समस्याएं तभी दूर होंगी जबकि सारे विश्व में शांति रहे और तनाव न हो।

माननीय सदस्यगण, इस अधिवेशन में आप आमदनी और खर्च के ब्यौरे तथा अगले माली साल के अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे, जो अर्थव्यवस्था को और पायदार तक एक निश्चित दिशा देने के नजरिये से महत्वपूर्ण है। नये लैजिस्लेटिव उपायों में जो आपके सामने पेश किये जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण वह है जिसका संबंध अर्बन लैंड की सीलिंग से है। आपके सामने कई चरणों में 34 बिल विचार के लिए हैं। इनमें से कुछ का बहुत महत्व है। आपके आगे एक सम्पूर्ण और कठिन प्रोग्राम है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि तल्ख बहस मुबाहसा और आन्दोलनों पर राष्ट्र की शक्ति जाया न करें, बल्कि भारत की जनता को, जिनमें चुनौतियों का मुकाबला करने की पूरी क्षमता है, रचनात्मक और साहसपूर्ण नेतृत्व दें।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।